

18.1 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(च) बोर्ड को अधिकृत करता है कि, संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर कोई भी शहरी क्षेत्र उसकी स्थान, जनसंख्या तथा विकास की समर्थता को ध्यान में रखते हुए चुना जाना चाहिए, जो कि काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके जिससे इस क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके ।

संकल्पात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र (सी.एम.ए.), जैसा क्षेत्रीय योजना-2001 में परिकल्पित है, ऐसा शहरी क्षेत्र होना चाहिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से काफ़ी दूरी पर स्थित हो तथा, जिसका अपना परिचित सुस्थित आधार और अंतर्निहित संभाव्यता हो जिससे व्यवहार्य स्वतंत्र विकास केन्द्र के रूप में प्रकाय कर सके । इस प्रकार अभिज्ञात काउंटर-मैग्नेट में भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता, परिवहन के संबंध में नोडालिटी होगी तथा परिवहन और संचार सुविधाओं के रूप में कोटि के भौतिक संपर्क होंगे ।

18.2 क्षेत्रीय योजना-2001 में काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों को निर्धारित की गई भूमिका

काउंटर-मैग्नेट की भूमिका जैसी क्षेत्रीय योजना-2001 में परिकल्पना की गई उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संदर्भ में दो विशिष्ट और पारस्परिक भूमिकाएं अदा करना था:

- (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अप्रवासी प्रवाह के लिए अंतर्बंधक बनना, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज़ी से विकास होने पर कम विकसित समीप के क्षेत्रों में प्रवासी को आकर्षित करने में सहायता कर सकता है;
- (ख) क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में, जो कुछ समय की अवधि में उनकी अपनी स्थापनाओं के पश्चात् क्षेत्रों में शहरीकरण का संतुलित पैटर्न हासिल कर सकेंगे ।

18.3 क्षेत्रीय योजना-2001 में काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की पहचान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों को अनुसरणित करते हुए आरंभ में दिल्ली से 100-400 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले 36 शहरों पर विचार किया गया और उनके आकार एवं स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, कार्यरत व्यक्तियों की भागीदारी अनुपात, जनसंख्या घनत्व तथा भौगोलिक घटकों जैसे सुगमता, आप्रवासी गलियारों के साथ सर्वसमता एवं क्षेत्र में अन्य दावेदारों से निकटता पर विश्लेषण किया गया । इन घटकों के विश्लेषण के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श एवं परामर्श के बाद, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए आगे की संवीक्षा के लिए संभावित दावेदारों के रूप में निम्नलिखित शहरी केन्द्रों की सिफारिश की गई:

- क) हरियाणा में हिसार, यमुना नगर, अम्बाला तथा करनाल
- ख) मध्य प्रदेश में ग्वालियर
- ग) पंजाब में पटियाला, भटिंडा तथा लुधियाना

18

COUNTER MAGNET AREAS

18.1 BACKGROUND

Section 8(f) of the NCR Planning Board Act, 1985 empowers the Board to select, in consultation with the State Governments concerned, any urban area outside NCR having regard to its location, population and potential for growth, which may be developed as Counter-Magnet Area in order to achieve the objectives of the Regional Plan.

Conceptually Counter-Magnet Areas (CMAs) to NCR, as envisaged in Regional Plan-2001, should be such urban areas as may be located sufficiently away from NCR and, should have its known established roots and inherent potentials to function as viable independent growth foci. Such identified Counter-magnets would have the attributes of physical, social and economic viability, nodality with respect to transportation network and have the quality of physical linkages in the form of transportation and communications facilities.

18.2 ASSIGNED ROLE OF COUNTER-MAGNET AREAS IN REGIONAL PLAN-2001

The role of Counter-magnets as envisaged in Regional Plan-2001 was to play two distinctive and mutually complementary roles in the context of NCR:

- a) As interceptors of migratory flows into NCR, which may escalate, as the accelerated development of NCR would provide a pull to migrants from the less developed adjoining areas;
- b) As regional growth centres, which would be able to achieve a balanced pattern of urbanisation in the region of their own setting over a period of time.

18.3 IDENTIFICATION OF COUNTER-MAGNET AREAS IN REGIONAL PLAN-2001

Keeping in with the objectives of the NCR Planning Board Act, 1985 initially 36 cities falling within the range 100-400 kms from Delhi were considered and analysed in respect of their size and status, population growth, work force participation ratio, population density and the spatial parameters like accessibility, congruence with immigration corridors and proximity to other contenders in the region. Based on the analysis of these parameters and after discussions and consultations with the State Governments, the following urban centres were recommended as possible contenders for further scrutiny to decide the counter-magnet areas:

- a) Hissar, Yamuna Nagar, Ambala and Karnal in Haryana
- b) Gwalior in Madhya Pradesh
- c) Patiala, Bhatinda and Ludhiana in Punjab

- घ) राजस्थान में कोटा, सीकर तथा अजमेर
ङ) उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा इलाहाबाद

संतुलित दिशात्मक विस्तार के हित में, बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए काउंटर-मैग्नेट्स के रूप में निम्नलिखित केन्द्रों को अंतिम रूप से चुना गया (मानचित्र 18.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र):

1. हरियाणा में हिसार
2. मध्य प्रदेश में ग्वालियर
3. पंजाब में पटियाला
4. राजस्थान में कोटा
5. उत्तर प्रदेश में बरेली

18.4 क्षेत्रीय योजना-2001 के लिए नीति दिशा-निर्देश

काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के विकास के लिए संबंधित सरकारों तथा बोर्ड द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में विस्तृत नीति दिशा-निर्देश क्षेत्रीय योजना-2001 में अनुबंधित किए गए हैं। राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों ने आर्थिक आधार प्रकार्यों तथा भौतिक एवं सामाजिक संरचना को सुदृढीकरण करने के लिए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है। संबंधित राज्य सरकारों ने प्रस्ताव किया कि काउंटर-मैग्नेट शहरों में स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों की संगठनात्मक क्षमताओं को सुदृढ करने के लिए कदम उठाएंगे तथा विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया करेंगे। केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने प्रस्ताव किया कि काउंटर-मैग्नेट नगरों के विकास के लिए क्षेत्रीय संपर्कों (परिवहन तथा संचार आदि) को सुदृढीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करेंगे।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां अपेक्षित थी ताकि काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता के लिए योग्य बनाया जा सके:

- i) काउंटर-मैग्नेट नगर की विकास योजना को अंतिम रूप देना।
- ii) नगर स्तर पर परियोजना अनुमोदन समिति का गठन करना।
- iii) वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।
- iv) काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के लिए विकास निधि में राज्य सरकार द्वारा अपना बराबरी का हिस्सा आबंटित करना।

18.5 काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों में विकास की स्थिति

क्षेत्रीय योजना-2001 में प्रस्तावित पांच काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि इस योजना की नीतियां अप्रवासी रूख को दिल्ली से दूर संभावित शहरीकरण वाले अभिजात काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की तरफ मोड़ने की होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी तरह की प्रेरित जनसंख्या वृद्धि से दिल्ली की जनसंख्या की वृद्धि गति दर बढ़ जाएगी।

अधिकांश मामलों में, राज्य सरकारें ने काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के संदर्भ में पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उल्लेखित आवश्यक कार्यवाही का सफल प्रबंध कर पाई हैं। ग्वालियर तथा पटियाला के काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों ने अब तक अधिकतम क्रमशः 61 करोड़ रुपये तथा 42.48 करोड़ रुपये ऋण सहायता ली है। उसके बाद बरेली द्वारा 20 करोड़ रुपये लिये गए हैं। कोटा ने केवल 2 करोड़ रुपये की मामूली ऋण सहायता प्राप्त की है और हिसार ने अभी तक कोई ऋण सहायता नहीं ली है।

- d) Kota, Sikar and Ajmer in Rajasthan
- e) Bareilly, Moradabad, Saharanpur and Allahabad in Uttar Pradesh

In the interest of balanced directional spilt, the following centres were finally selected as counter-magnets to NCR by the Board (Map 18.1 National Capital Region: Counter Magnet Areas):

- 1) Hissar in Haryana
- 2) Gwalior in Madhya Pradesh
- 3) Patiala in Punjab
- 4) Kota in Rajasthan
- 5) Bareilly in Uttar Pradesh

18.4 POLICY GUIDELINES OF REGIONAL PLAN-2001

Development of Counter-Magnet Areas would require coordinated efforts of the State and Central Governments and the National Capital Region Planning Board. The broad policy guidelines for development of Counter-Magnet Areas in terms of the role to be played by the respective Governments and the Board have been stipulated in Regional Plan-2001. The State Governments/implementing agencies proposed to prepare integrated development programme for the Counter-Magnet Areas for strengthening the economic base functions and upgradation of physical and social infrastructure. The concerned State Governments proposed to take steps to strengthen organisational capacities of the local bodies/development authorities in the counter-magnet cites and provide adequate financial resources for development. The Central Government and NCR Planning Board proposed to provide financial assistance for strengthening of regional linkages (transport and communications etc.) for development of counter-magnet towns.

Respective State Governments were required to take the following actions in order to make the CMAs eligible for assistance from the NCR Planning Board:

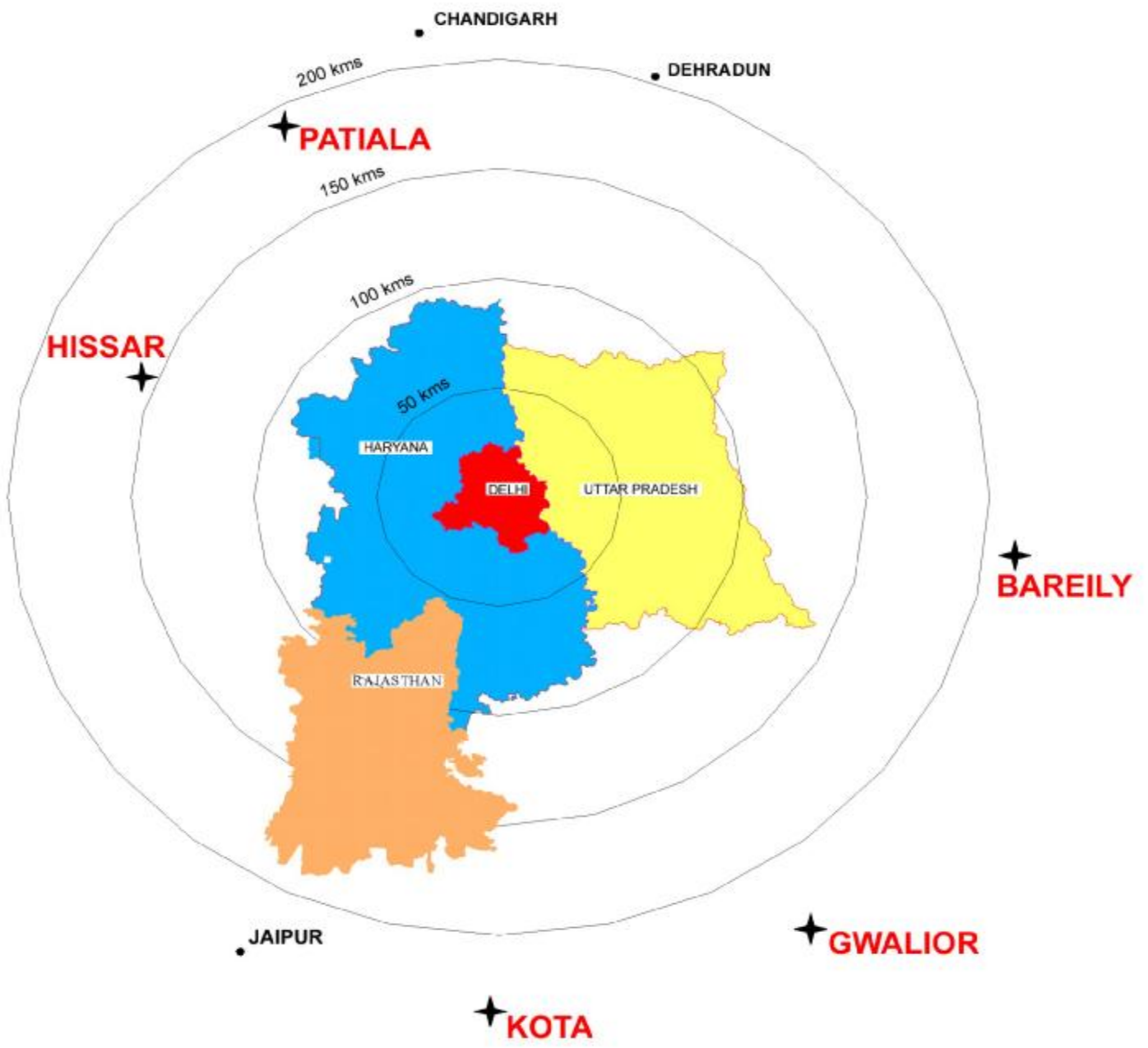
- i) Finalisation of the Development Plan for the counter-magnet town.
- ii) Constitution of Project Sanctioning Committee at the town level.
- iii) Preparation of Annual Action Plan.
- iv) Allocation by the State Government of its matching share in the Development Fund for the counter-magnet areas.

18.5 STATUS OF DEVELOPMENT OF COUNTER-MAGNET AREAS

A review of five Counter-Magnet Areas proposed in the Regional Plan-2001 suggested that the policies of the Plan should be to divert migration streams away from Delhi to the identified Counter-Magnet Areas with urbanization potential because any induced population growth in NCR would lead to the accelerated rate of growth of population of Delhi.

In most of the cases, the State Governments did manage to take the required actions referred to in the foregoing para in respect of the Counter-Magnet Areas. The counter-magnet towns of Gwalior and Patiala have so far availed of maximum loan assistance of Rs.61 crores and Rs.42.48 crores respectively followed by Bareilly at Rs.20 crores. Kota has obtained only a marginal loan assistance of Rs.2 crores and Hissar has not yet taken any loan assistance.

NATIONAL CAPITAL REGION COUNTER-MAGNET TOWNS



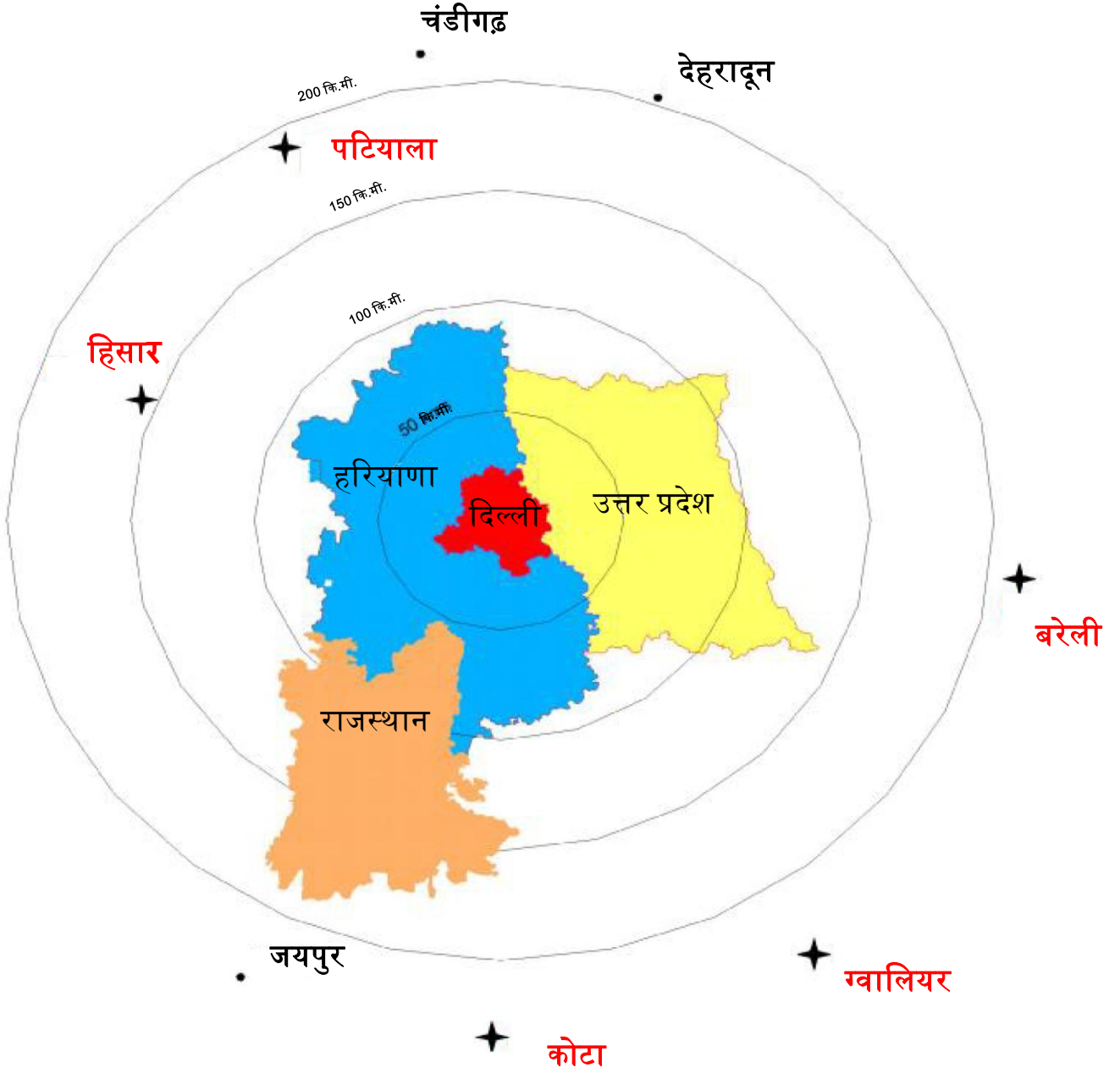
LEGEND

Counter Magnet Town ✦

 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
MAP 18.1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र

उ.



संकेतिका

काउंटर-मैग्नेट नगर



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
मानचित्र 18.1

18.6 काउंटर-मैग्नेट विकास का विश्लेषण

क्षेत्रीय योजना-2001 की अवधि के दौरान काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के विकास के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :

- (i) काउंटर-मैग्नेटस दिल्ली में अपने-अपने राज्यों से आप्रवासी प्रवाह को कम करने की निर्धारित भूमिका मुख्यतः दूरी घटक और विकास के लिए आबंटित धन के अभाव की वजह से अदा नहीं कर सके ।
- (ii) काउंटर-मैग्नेटस की विकास की नीति पर अधिक कारगर तरीके से अनुसरण करने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार से परामर्श करके, उत्तर प्रदेश में एक से अधिक ऐसी बस्ती की पहचान करी जाए, जहां से लगभग 49% आप्रवासी दिल्ली को आते हैं ।

18.7 प्रस्ताव तथा सिफारिशें

काउंटर-मैग्नेटस की क्षेत्रीय योजना-2001 में समीक्षा के आधार पर, यह महत्वपूर्ण है कि काउंटर-मैग्नेटस की विकास की नीति पर अधिक कारगर तरीके से अनुसरण किया जाए । इसलिए, यह सुझाव है कि राज्य सरकार से परामर्श करके, उत्तर प्रदेश में एक से अधिक ऐसी बस्ती की पहचान करी जाए, जहां से लगभग 49% आप्रवासी दिल्ली को आते हैं ।

साथ ही काउंटर-मैग्नेटस को उनकी निर्धारित भूमिकाओं को अधिक कारगर रूप से समर्थ बनाने के उत्तरदायित्व के लिए, उनकी भावी विकास की दिशा में निम्नलिखित पहलुओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए:

क) आर्थिक आधार प्रकार्यों का सुदृढीकरण करना

आप्रवासी के लिए अंतर्राष्ट्रिक के रूप में काउंटर-मैग्नेटस की सफलता अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को सृजन करने के लिए सम्पूर्ण रूप से उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी ताकि यह आसपास के क्षेत्रों की श्रमिक-आयु दल को पर्याप्त अवसर मुहैया करा सके जो अन्यथा दिल्ली की ओर आप्रवास करने के लिए प्रलोभित होगी । काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) के रूप में घोषित किया जाए जिससे उनमें आर्थिक निवेश को आकर्षित किया जा सके और राज्य सरकारों तथा वाणिज्य एवं उद्योग केन्द्रीय मंत्रालय संयुक्त रूप से परियोजनाएं ले सकें । साथ ही, अन्य भौतिक अवसंरचना तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी चाहिए तदनुसार इन काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों में उद्योग आकर्षित किया जा सकें ।

ख) भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का उन्नयन करना

काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों में संकेतिक आर्थिक अवसंरचना को सहयोग और संपोषित बनाने के लिए इन क्षेत्रों में बहुत उच्च श्रेणी की भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना मुहैया करने की ज़रूरत होगी जिसके लिए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और राज्य सरकारों को संयुक्त परियोजनाएं तैयार करनी होंगी जिनको योजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रों के लिए प्रचलित वित्तपोषण पैटर्न के जरिए वित्तीय सहायता दी जा सके ।

यहां विशेषज्ञता वाले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत गतिविधियां जैसे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के केन्द्र अर्थात् व्यावसायिक कॉलेजों को स्थापित किया जा सके और साथ ही साथ पर्यटन गंतव्यों को प्रोत्साहित किया जा सके ।

ग) क्षेत्रीय संपर्कों का सुदृढीकरण करना

इन काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित आर्थिक तथा भौतिक अवसंरचना का अर्थपूर्ण उपयोग करने के लिए, उनकी आंतरिक क्षेत्रों के साथ ही साथ अन्य महानगर केन्द्रों के साथ बहुत सशक्त संपर्कों को स्थापित करने की ज़रूरत होगी । रेल, जहाज़रानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग के साथ ही साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय मंत्रालयों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर योजनाबद्ध तरीके से इन काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार संपर्कों में सुधार लाने के लिए ढेर सारे प्रयास करने होंगे ।

18.6 ANALYSIS OF CMA DEVELOPMENT

The analysis of development of the CMAs during the tenure of Regional Plan-2001 has brought out the following observations:

- (i) The Counter-magnets have not played the assigned role in reducing the flow of migrants from the respective States to Delhi largely due to distance factor and paucity of funds allocated for their development.
- (ii) In order to pursue the policy of development of counter-magnets in a more effective manner, it is suggested that more than one such settlement be identified in UP, in consultation with the State Government, from where 49% migrant come to Delhi.

18.7 PROPOSALS AND RECOMMENDATIONS

Based on the review of the Regional Plan-2001 on Counter-Magnets, it is important to pursue the policy of development of counter magnets in a more effective manner. Therefore, it is suggested that more than one such settlement be identified in UP, in consultation with the State Government, from where about 49% migrant come to Delhi.

Further in order to make the counter-magnets capable to undertake their assigned roles more effectively, their future development must be directed to cover the following aspects:

a) Strengthening of Economic Base Functions

The success of the counter-magnets as interceptors of migration entirely depends upon their capacity to generate more and more economic activities so that they can provide adequate opportunities to the working-age group population of the surrounding areas, who would otherwise be tempted to migrate to Delhi. The counter-magnet areas may be declared as Special Economic Zone (SEZ) for attracting economic investment therein and projects be taken up jointly by the State Governments and the Central Ministry of Commerce and Industry. Simultaneously, other physical infrastructure and fiscal incentives could be provided so as to attract industry to these Counter-Magnet Areas.

b) Upgradation of Physical and Social Infrastructure

In order to support and sustain the economic infrastructure suggested in the counter-magnet areas, physical and social infrastructure of a very high order needs to be provided in these areas for which the Counter-Magnet Area Development Authorities and the State governments will have to prepare joint projects which could be financially supported by the NCRPB through its prevailing funding pattern for NCR areas.

Specialized social, cultural and institutional activities like universities and centre of higher education i.e., professional colleges could be established as well as encourage development of tourist destinations.

c) Strengthening of Regional linkages

In order to make meaningful use of the economic and physical infrastructure proposed to be developed in these counter-magnet areas, their linkages with the hinterland as well as with the other important metropolitan centres need to be very strong. The Central Ministries of Railways, Shipping, Road Transport and Highways as well as Communications and Information Technology will have to put in a lot of effort in improving the transport and communication linkages in these counter magnet areas in a planned manner within a specified time frame.